

चीनी उत्पादन तीन करोड़ टन गन्ना एरियर 19 हजार करोड़ सरकार से वर्ष 2015-16 की तर्ज पर मदद की गुहार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड तीन करोड़ टन को छू रहा है, जिससे गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 19 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इससे चीनी मिलों के साथ गन्ना किसानों की मुश्किलें भी सातवें आसमान पर पहुँच गई हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने उद्योग के समक्ष पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

चीनी उद्योग संगठन ने सरकार से अतिरिक्त चीनी उत्पादन के हिसाब से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए मदद की अपील की है। यह फार्मूला सरकार ने वर्ष 2015-16 में अपनाया था, जिससे चीनी उद्योग को बहुत राहत मिली थी। उस समय इस फार्मूले के तहत किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने पर 4.50 रुपये सीधे खाते में दिए गए थे। मूल्य का यह अंतर गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक, 15 अप्रैल तक मिलों पर कुल 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो चुका है। इसमें पिछले वर्षों का 697 करोड़ रुपये का

उत्पादन और एरियर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, इस्मा ने उद्योग के समक्ष पैदा हुए संकट से निपटने को हस्तक्षेप की मांग की

राज्यवार एरियर (करोड़ रु. में)

उत्तर प्रदेश	8,869
कर्नाटक	2,420
महाराष्ट्र	2,213



बकाया शामिल नहीं है।

चीनी उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीते चीनी वर्ष (अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017) के दौरान कुल 2.03 करोड़ टन चीनी

का उत्पादन हुआ था, जबकि चीनी की घरेलू खपत के लिए कुल 2.50 करोड़ टन चीनी की जरूरत पड़ती है। इस्मा के मुताबिक 15 अप्रैल, 2018 तक चीनी का कुल उत्पादन 2.99 करोड़ टन हो गया है। चीनी उत्पादन का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कुल 1.05 करोड़ टन चीनी तैयार हुई है। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन का यह आंकड़ा 1.04 करोड़ टन को छू गया है। कर्नाटक में चीनी मिलों में पेरई बंद हो चुकी है। यहां कुल 36 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

चीनी का कुल उत्पादन घरेलू खपत के मुकाबले 50 लाख टन अधिक हो चुका है। गन्ने की अच्छी फसल और चीनी के भारी उत्पादन के चलते जिन बाजार में चीनी का मूल्य पिछले चार-पांच महीने से दबाव में है। इस्मा के मुताबिक बाजार में चीनी का मूल्य उत्पादन लागत के मुकाबले नौ रुपये प्रति किलो कम चल रहा है। नतीजा यह हुआ कि मिलें भारी घाटे में चली गई हैं। इसके चलते गन्ना किसानों का भुगतान संभव नहीं रह गया है।

Vainik Jagran

18-4-18

✓